TO JOIN OUR UPSC PAID GROUP

WHATSAPP GROUP ➡ 9818323004

THE HINDU ANALYSIS – 12 JUNE 2023

संपादकीय 1: बेहतर भारत-नेपाल संबंधों के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण

प्रसंग

- नेपाल के लोकतंत्र, शासन और स्थिरता के लिए कठिन चुनौतियों और प्रतीत होने वाले असाध्य द्विपक्षीय अड़चनों के बावजूद, नेपाल और भारत के प्रधानमंत्रियों ने दिखाया है कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण और पारस्परिक संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों को फिर से सक्रिय कर सकती है।

- नेपाल के प्रधान मंत्री, पुष्प कमल दहल प्रचंड की वर्तमान कार्यकाल में पदभार ग्रहण करने के बाद भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा इस अर्थ में उल्लेखनीय है। COVID-19 के बाद की दुनिया, वर्तमान वास्तविकताओं के साथ-साथ विशाल अवसरों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से प्रेरित होकर, भारत और नेपाल राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और विकासात्मक सहयोग को कवर करने वाले द्विपक्षीय एजेंडे के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा करने में सक्षम थे।

भारत-नेपाल संबंध:

- सदियों से फैले भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों/संबंधों के कारण नेपाल भारत की विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है।

- भारत और नेपाल वर्तमान समय के नेपाल में स्थित बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी के साथ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं।

- दोनों देशों के बीच विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से घनिष्ठ संबंध हैं, जिसे रोटी-बेटी का रिश्ता के नाम से जाना जाता है।

- 1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।

UPSC DESIRE WHATSAPP GROUP 8054028168

दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र

- **व्यापार और अर्थव्यवस्था** : वित्त वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 7 बिलियन अमरीकी डालर को पार करने के साथ भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना हुआ है।

- **कनेक्टिविटी : भारत व्यापार और पारगमन व्यवस्था के ढांचे के भीतर कार्गो की आवाजाही के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करना चाहता है, नेपाल के लिए समुद्र तक अतिरिक्त पहुंच प्रदान करना इसे सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) को सागर (हिंद महासागर) से** जोड़ना है।

- **रक्षा सहयोग** : द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में उपकरण और प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से नेपाली सेना के आधुनिकीकरण में सहायता शामिल है। 2011 से भारत हर साल नेपाल के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है जिसे **सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है।**

- **मानवीय सहायता:** नेपाल संवेदनशील पारिस्थितिक नाजुक क्षेत्र में स्थित है जो भूकंप और बाढ़ के प्रति संवेदनशील है, जिससे जीवन और धन दोनों को भारी नुकसान होता है, जिससे यह भारत की मानवीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है।

- **बहुपक्षीय भागीदारी: भारत और नेपाल** BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल), BIMSTEC (बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल), गुट निरपेक्ष आंदोलन, और **सार्क** (साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर फॉर) जैसे कई बहुपक्षीय मंच साझा करते हैं। क्षेत्रीय सहयोग) आदि।

भारत-नेपाल परियोजनाएं:

- महाकाली संधि (6,480 मेगावाट)
- अपर करनाली परियोजना (900 मेगावाट)
- अरुण तीन परियोजनाएं (900 मेगावाट)
- सेती नदी (SR6) परियोजना

UPSC DESIRE WHATSAPP GROUP 8054038108

चुनौतियां

- **प्रादेशिक विवाद** : भारत-नेपाल संबंधों में मुख्य चुनौतियों में से एक कालापानी सीमा का मुद्दा है। ये सीमाएँ 1816 में अंग्रेजों द्वारा तय की गई थीं, और भारत को वे क्षेत्र विरासत में मिले थे जिन पर अंग्रेजों ने 1947 में क्षेत्रीय नियंत्रण का प्रयोग किया था।

- **शांति और मित्रता संधि के मुद्दे** : 1950 की शांति और मित्रता की संधि की मांग 1949 में नेपाली अधिकारियों द्वारा ब्रिटिश भारत के साथ उनके विशेष संबंधों को जारी रखने और उन्हें एक खुली सीमा और भारत में काम करने का अधिकार प्रदान करने के लिए की गई थी। लेकिन आज, इसे एक असमान रिश्ते और एक भारतीय थोपने के संकेत के रूप में देखा जाता है।

- **चीन का हस्तक्षेप** हाल के वर्षों में, नेपाल भारत के प्रभाव से दूर हो गया है, और चीन ने धीरे-धीरे निवेश, सहायता और ऋण के साथ जगह भर दी है।

- **आंतरिक सुरक्षा**: यह भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि भारत-नेपाल सीमा वास्तव में खुली और हल्की निगरानी वाली है जिसका भारत के उत्तर पूर्वी भाग के आतंकवादी संगठनों और विद्रोही समूहों द्वारा शोषण किया जाता है, जैसे प्रशिक्षित कैडरों की आपूर्ति, नकली भारतीय मुद्रा।

आगे बढ़ने का रास्ता

- आज आवश्यकता क्षेत्रीय राष्ट्रवाद पर बयानबाजी से बचने और शांत संवाद के लिए नींव रखने की है, जहां दोनों पक्ष संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वे यह पता लगाते हैं कि क्या संभव है। भारत को नेबरहुड फर्स्ट नीति के जड़ जमाने के लिए एक **संवेदनशील और उदार भागीदार बनने की जरूरत है।**

- भारत को लोगों से लोगों के जुड़ाव, नौकरशाही जुड़ाव के साथ-साथ राजनीतिक बातचीत के मामले में नेपाल के साथ और अधिक सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए।

UPSC DESIRE WHATSAPP GROUP 8054036168

संपादकीय 2: अटूट ध्यान

प्रसंग

- मौद्रिक **नीति समिति (एमपीसी) का** नवीनतम निर्णय, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक तंगी में विराम को बढ़ाने के लिए, जबकि समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मुद्रास्फीति को सामने रखने के लिए दर सेटिंग पैनल के आश्वस्त संकल्प को दर्शाता है और नीति के प्रति इसके दृष्टिकोण का केंद्र।

विवरण

- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट रूप से कहा था कि "अर्थव्यवस्था की अपनी क्षमता का एहसास करने की क्षमता के लिए मौद्रिक नीति का सबसे अच्छा योगदान मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है"।

- मूल्य स्थिरता पर एमपीसी का हाल का अटूट ध्यान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने जनादेश द्वारा सूचित किया गया है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे जनवरी 2021 से ही वास्तविक रूप से प्राप्त करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ा है।

- विशेष रूप से, श्री दास ने इस मानसून के दौरान एल नीनो की स्थिति, बेरोकटोक भू-राजनीतिक तनाव, चीनी, चावल और कच्चे तेल सहित अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों पर अनिश्चितता और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के मद्देनजर वर्षा के स्थानिक और अस्थायी वितरण को हरी झंडी दिखाई। एमपीसी के मुद्रास्फीति अनुमानों के लिए ऊपरी जोखिम के रूप में।

- आरबीआई के नीतिगत दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाला एक अन्य प्रमुख कारक इसका विश्वास है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने पर निरंतर ध्यान देने के बाद समष्टि आर्थिक बुनियादी सिद्धांत मजबूत हुए हैं।

आरबीआई की मौद्रिक नीति

- मौद्रिक नीति ब्याज दरों, धन की आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता के मामलों में केंद्रीय बैंक - यानी भारतीय रिजर्व बैंक - की नीति को संदर्भित करती है।

- यह मौद्रिक नीति के माध्यम से है, आरबीआई देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है।

- RBI अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मौद्रिक साधनों जैसे **REPO दर, रिवर्स RERO दर, SLR, CRR आदि का उपयोग करता है।**

UPSC DESIRE WHATSAPP GROUP 8054038168

विस्तारवादी और संविदात्मक मौद्रिक नीति

- मौद्रिक नीति विस्तारवादी या संकुचनकारी हो सकती है।
- एक **विस्तारित मौद्रिक नीति** एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के विस्तार (बढ़ाने) पर केंद्रित है। प्रमुख ब्याज दरों को कम करके एक विस्तारित मौद्रिक नीति लागू की जाती है जिससे बाजार की तरलता बढ़ जाती है।
- एक **संकुचनकारी मौद्रिक नीति** एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करने (घटाने) पर केंद्रित है। प्रमुख ब्याज दरों को बढ़ाकर इस प्रकार बाजार की तरलता को कम करके एक संकुचनकारी मौद्रिक नीति लागू की जाती है।

भारत की मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य

- मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए **मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।** सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है।
- मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। भारत सरकार हर पांच साल के लिए एक मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के संबंध में परामर्श प्रक्रिया में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में मौजूदा मुद्रास्फीति-लक्षित ढांचा प्रकृति में लचीला है।

लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा (FITF)

- अब भारत में एक लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा है (2016 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 में संशोधन के बाद)।
- संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम प्रत्येक पांच साल में एक बार रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए प्रदान करता है।
- केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए लक्ष्य के रूप में 4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को अधिसूचित किया है, जिसमें 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा और 2 प्रतिशत की निचली सहनशीलता सीमा है। सेंट।

निष्कर्ष

- मूल्य स्थिरता आखिरकार एक सार्वजनिक वस्तु है और टिकाऊ अपस्फीति को प्राप्त करना एक गैर-परक्राम्य लक्ष्य बना रहना चाहिए, विशेष रूप से बढ़ती आय असमानता और उच्च स्तर की बेरोजगारी के बीच।

UPSC DESIRE WHATSAPP GROUP 8054038168

Click here upsc.desire

Click here everyday.current.gk

UPSC.DESIRE WHATSAPP GROUP 8054